



Daily 3 most important classes



5 am -> 10 min current affairs show



7 am -> The Hindu Analysis



8 am -> Daily SSC CGL/ CHSL Specific GK class

Download Class24 Application



Class Pdf



10 Question Test Related To This Class

Complete Gk/Gs Notes BY BHUNESH SIR



Step-1



Step-3

Step-4

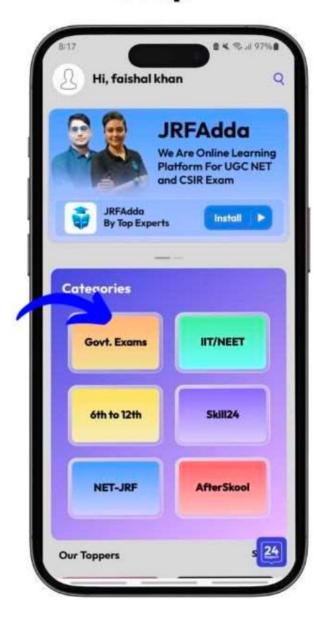




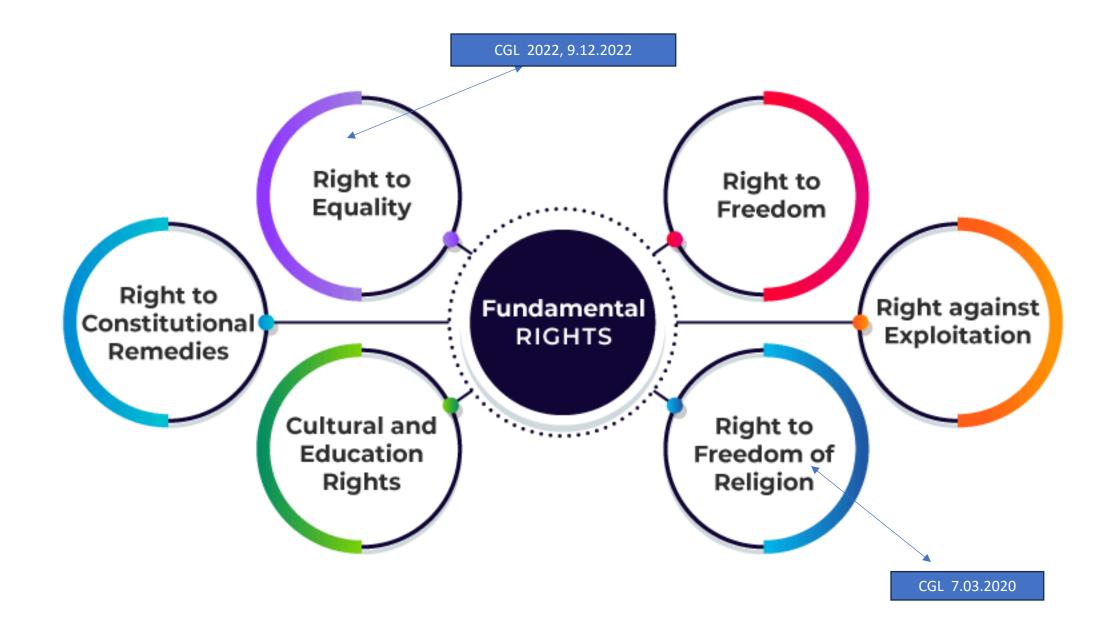






Table of content / सामग्री की तालिका

- 1. Why Article 32 is Important
- 2. Articles 32 in Short
- 3. Articles 32 in Details
- 4. Cases related
- 5. Facts



भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS सांविधानिक उपचारों का अधिकार / Right to Constitutional Remedies

अनुच्छेद	विवरण
32	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार / Remedies for enforcement of rights conferred by this Part
33	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति / Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc.
34	जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन / Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area
35	इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान / Legislation to give effect to the provisions of this Part

PATIII: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS सांविधानिक उपचारों का अधिकार / Right to Constitutional Remedies

- 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।
- अनुच्छेद ३२: इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- Dr. Bhimrao Ambedkar has called the 'right to constitutional remedies' the soul of the Constitution.
- Article 32: The right to apply in the Supreme Court has been given by appropriate proceedings to enforce fundamental rights under it.

CGL - 30.08.2016, 19.06.2011, 19.05.2013, Mains 22, 6.03.2023. CHSL- 20.10.2013, 8.03.2018, 14.10.2020,12.04.21

भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS सांविधानिक उपचारों का अधिकार / Right to Constitutional Remedies

अनुच्छेद 32 के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को पांच तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न हैं:

- १. बंदी प्रत्यक्षीकरण
- २. परमादेश
- 3. प्रतिषेध लेख
- 4. उत्प्रेषण
- 5. अधिकार पृच्छा लेख

With reference to Article 32, the Supreme Court has been empowered to remove five types of writ which are as follows:

- 1. Habeas Corpus
- 2. Mandamus
- 3. Prohibition
- 4. Certiorari
- 5. Writ of Quo Warranto

WRITS UNDER ARTICLE 32

O 1
Habeas corpus

"To bring a person arrested to the court"

· Against individual as well as state

"A command to perform its duty"

- Against officers, public servants & govt
- Also against lower court
- Not against president or governor.
- Also issued to instruct govt to not enforce an unconstitutional law.

02
Mandamus

03
Prohibition

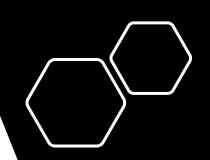
- Only to a lower court.
- To keep them in their jurisdiction.
- Against judicial and quasi-judicial bodies.

- Judicial & quasi-judicial bodies.
- · Administrative authorities.
- Quashes the other of lower court
- and pulls the case to itself.
 Not against legislative bodies

04
Mandamus

05
Quo Warranto

- Substantive public office of permanent character.
- Enquire the legality of claims of a person to a public office.
- Not against a ministerial office.
- Anyone & not just the person aggrieved can seek this writ.



What is a Writ Petition?

- A writ petition is essentially a court petition for extraordinary review, asking a court to intervene in a lower court's decision.
- Under the Indian legal system, jurisdiction to issue 'prerogative writs' is given to the Supreme Court, and to the High Courts of Judicature of all Indian states.
- Parts of the law relating to writs are set forth in the Constitution of India.

रिट याचिका क्या है?

- एक रिट याचिका अनिवार्य रूप से असाधारण समीक्षा के लिए एक अदालत की याचिका है, जो एक अदालत को निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए कहती है।
- भारतीय कानूनी प्रणाली के तहत, सर्वोच्च विशेषाधिकार जारी करने का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय, और सभी भारतीय राज्यों के न्यायिक उच्च न्यायालयों को दिया जाता है।
- राइट्स से संबंधित कानून के कुछ हिस्सों को भारत के संविधान में निधिरित किया गया है।

Power with respect to writ jurisdiction

- Limited to fundamental rights for supreme court (narrower), but both fundamental rights and Legal rights for High Courts.
- For Supreme Court territory is wider as includes entire India
- High Court may refuse to issue writs and 226 is not fundamental right, but Article 32 being a fundamental right itself, Supreme Court cannot (Hence, Supreme Court is ultimate defender and guarantor of fundamental rights.

अधिकार क्षेत्राधिकार के संबंध में शक्ति

- सर्वोच्च न्यायालय (संकीर्ण) के लिए मौलिक अधिकारों तक सीमित है, लेकिन उच्च न्यायालयों के लिए मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों हैं।
- पूरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र व्यापक हैं
- उच्च न्यायालय रिट जारी करने से इनकार कर सकता है और 226 मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है (इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर है।

Habeas Corpus: 'to have the body of'. Order issued by the court to a person who has detained another person, to produce the body of the latter before it. Examines the cause and legality of detention. Set free it detention is found to be illegal. Protection of individuality liberty against detention.

It is both against State and Private Citizen and Principle of Locus Standi does not apply. Writ is not issued (a) lawful, (b) contempt of a legislature or a court, (c) detention is by a competent court, (d) outside the jurisdiction of the court.

हैबियस कॉर्पसः 'के शरीर के लिए'। अदालत द्वारा एक व्यक्ति को जारी किया गया आदेश जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, इससे पहले के शरीर का उत्पादन करने के लिए। निरोध के कारण और वैधता की जांच करता है। निः शुल्क सेट करें यह निरोध अवैध पाया जाता है। नजरबंदी के खिलाफ व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण।

यह स्टेट और प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ है और Locus Standi का सिद्धांत लागू नहीं होता है। विधायिका या अदालत की अवमानना (क) वैध, (ख) अवमानना जारी नहीं की जाती है, (ग) निरोध सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाता है, (घ) न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। Mandamus: 'we command'. It is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform.

Filed only by aggrieved person (Principle of Locus Standi applies).

The writ of mandamus cannot be issued (a) against a private individual or body; (b) to enforce departmental instruction that does not possess statutory force; (c) when the duty is discretionary and not mandatory; (d) to enforce a contractual obligation; (e) against the president, governor, chief justice of a high court acting in judicial capacity.

मंडामस: 'हम आजा देते हैं'। यह एक सार्वजनिक अधिकारी को अदालत द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहता है कि वह विफल रहा है या प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है।

केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर की गई (प्रिंसिपल ऑफ लॉकस स्टैंडी लागू होती है)।

मंडम की रिट जारी नहीं की जा सकती है (ए) एक निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ; (ख) वैधानिक बल के अधिकारी विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए नहीं; (ग) जब कर्तव्य विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है; (घ) एक संविदात्मक दायित्व लागू करने के लिए; (() न्यायिक क्षमता में काम करने वाले उच्च न्यायालय के अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ। **Prohibition:** 'to forbid'. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding/usurping its jurisdiction.

The writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities

- निषेध: 'मना करना'। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि बाद वाले को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक / रोक दिया जा सके।
- निषेध की रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है

- Certiorari: 'to be certified/informed'. It is issued by a higher to a lower court/tribunal either to transfer a case or to squash the order. It is issued on the grounds of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law. Thus, unlike prohibition, which is only preventive, certiorari is both preventive as well as curative.
- Till recently, the writ of certiorari could be issued against judicial, quasijudicial authorities and administrative authorities. Like prohibition, certiorari is also not available against legislative bodies and private individuals or bodies.
- सर्टिओरीरी: 'प्रमाणित / सूचित किया जाना'। यह एक निचली अदालत / द्रिब्यूनल को उच्चतर द्वारा या तो किसी मामले को स्थानांतरित करने या आदेश को स्क्वैश करने के लिए जारी किया जाता है। यह अधिकार क्षेत्र की अधिकता या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की तुर्रि के आधार पर जारी किया जाता है। इस प्रकार, निषेध के विपरीत, जो केवल निवारक है, सर्टिओरीरी दोनों निवारक के साथ-साथ उपचारात्मक भी है।
- हाल तक, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सर्टिफिकेट की रिट जारी की जा सकती थी। निषेध की तरह, प्रमाणित निकाय विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के खिलाफ भी उपलब्ध नहीं हैं।

Quo-warranto:

- 'by what authority or warrant'. It is issued by the court to enquire into the legality of claim of a person to a public office, preventing illegal usurpation of public office by a person.
- The writ can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character created by a statue of by the Constitution. It cannot be issued in cases of ministerial office or private office.

Quo-warranto:

- 'किस अधिकार या वारंट द्वारा'। यह अदालत द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है, जिससे किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय का अवैध रूप से उपयोग रोका जा सके।
- संविधान द्वारा एक स्थायी चरित्र के एक स्थायी चरित्र के एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यालय के मामले में ही रिट जारी की जा सकती है। इसे मंत्री कार्यालय या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है।

08.08.2017

Facts about Habeas Corpus in India:

- Supreme Court or High Court can issue this writ against both private and public authorities.
- Habeas Corpus can not be issued in the following cases:
 - When detention is lawful
 - When the proceeding is for contempt of a legislature or a court
 - Detention is by a competent court
 - Detention is outside the jurisdiction of the court

भारत में हैबियस कॉर्पस के बारे में तथ्य:

- सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों निजी और सार्वजनिक प्राधिकारियों के खिलाफ यह रिट जारी कर सकता है।
- निम्नलिखित मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जा सकता है:
 - जब नजरबंदी कानूनन है
 - जब कार्यवाही विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो
 - निरोध सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाता है
 - निरोध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है

Facts about Mandamus in India:

- Unlike Habeas Corpus, Mandamus cannot be issued against a private individual
- Mandamus can not be issued in the following cases:
- To enforce departmental instruction that does not possess statutory force
- To order someone to work when the kind of work is discretionary and not mandatory
- To enforce a contractual obligation
- Mandamus can't be issued against Indian President or State Governors
- Against the chief justice of a high court acting in a judicial capacity

भारत में मंडमों के बारे में तथ्य:

- हैबियस कॉर्पस के विपरीत, मंडामस को एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है
- निम्न मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है:
- विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जो वैधानिक बल के पास नहीं है
- किसी को काम करने का आदेश देना जब काम का प्रकार विवेकाधीन हो और अनिवार्य न हो
- एक संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए
- मंडामस को भारतीय राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है
- न्यायिक क्षमता में काम करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ

Facts about Prohibition in India:

- Writ of Prohibition can only be issued against judicial and quasi-judicial authorities.
- It can't be issued against administrative authorities, legislative bodies, and private individuals or bodies

भारत में निषेध के तथ्य:

- निषेधाजा केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है।
- यह प्रशासनिक अधिकारियों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है

Facts about Certiorari in India:

- Pre-1991: The writ of Certiorari used to be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities
- Post-1991: Supreme Court ruled that the certiorari can be issued even against administrative authorities affecting the rights of individuals
- It cannot be issued against legislative bodies and private individuals or bodies.

भारत में सर्टिफिकेट के बारे में तथ्य:

- 1991 से पहले: सर्टिफिकेट की रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती थी, न कि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ
- 1991 के बाद: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है
- इसे विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है।

Facts about Quo-Warranto in India:

- Quo-Warranto can be issued only when the substantive public office of a permanent character created by a statute or by the Constitution is involved
- It can't be issued against private or ministerial office
- Note: This writ gives the right to seek redressal to any individual other than the aggrieved person.

भारत में Quo-Warranto के बारे में तथ्य:

- Quo-Warranto केवल तभी जारी किया जा सकता है जब किसी स्थायी या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र का मूल सार्वजनिक कार्यालय शामिल हो
- इसे निजी या मंत्रिस्तरीय कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है
- नोट: यह रिट व्यथित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को निवारण का अधिकार देता है।

General Facts about Writs in India:

- Article 32 also empowers Parliament to authorize any other court to issue these writs
- Before 1950, only the High Courts of Calcutta, Bombay and Madras had the power to issue the writs
- Article 226 empowers all the high courts of India to issue the writs
- Writs of India are borrowed from English law where they are known as 'Prerogative writs'

भारत में लेखन के बारे में सामान्य तथ्य:

- अनुच्छेद ३२ इन अधिकारों को जारी करने के लिए किसी अन्य अदालत को अधिकृत करने के लिए संसद को भी अधिकार देता है
- 1950 से पहले, केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालय ही रिट जारी करने की शक्ति रखते थे
- अनुच्छेद २२६ भारत के सभी उच्च न्यायालयों को अधिकार जारी करने का अधिकार देता है
- भारत के लेखन को अंग्रेजी कानून से उधार लिया जाता है, जहाँ उन्हें ative Prerogative रिट्स 'के रूप में जाना जाता है।

Cases

Romesh Thapar vs State of Madras 1950 In this case Supreme Court observed that Article 32 guarantees a remedy for enforcing fundamental rights under the constitution of India.

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950-इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की अनुच्छेद 32 एक उपाय की गारंटी देता है के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करना भारत का संविधान.

Cases

•In L. Chandra Kumar vs Union of **India** and others case- According to the Supreme Court, Article 32 is the fundamental structure of the constitution and serves as an important function being हिस्सा होने के नाते एक महत्वपूर्ण कार्य करता the inseparable part.

एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य मामले में- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अनुच्छेद 32 संविधान की मौलिक संरचना है और अविभाज्य Cases

•In the S.P. Sampath Kumar V/S Union of India case— The Supreme Court of India held that Article 32 powers are part of the constitution of India framework.

एस.पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले में-भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 32 की शक्तियां भारत के संविधान ढांचे का हिस्सा हैं।

Complete Gk/Gs Notes BY BHUNESH SIR

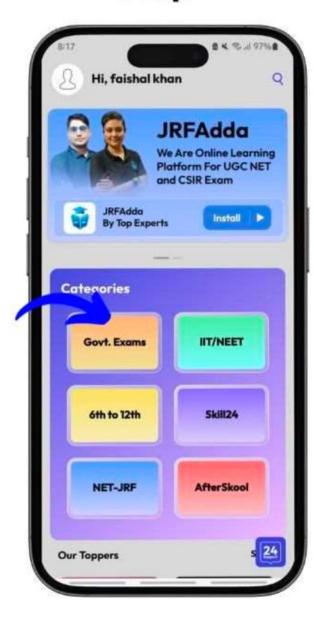


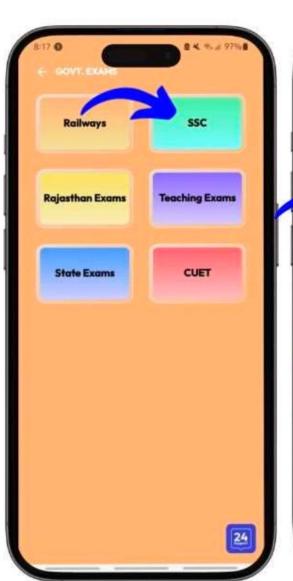
Step-1





Step-4









Download Class24 Application



Class Pdf



10 Question Test Related To This Class



Daily 3 most important classes



5 am -> 10 min current affairs show



7 am -> The Hindu Analysis



8 am -> Daily SSC CGL/ CHSL Specific GK class

Test with Every Class

